

प्रेषक,

सी० एस० नपलच्याल,
सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री भगत सिंह कोश्यारी,
मा० पूर्व मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

विषय :- मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारिण निर्णय के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मा० भूतपूर्व मुख्यमंत्रीगणों को आवंटित शासकीय आवासों के अध्यारोपित किराये के भुगतान के संबंध में।

दिनांक : 29 नवम्बर, 2016।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-1327/xxxii-2-2016-3(31)/2015, दि० 17, अक्टूबर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको आवंटित शासकीय आवास को रिक्त करने तथा आवास के अध्यारोपित किराये की आगणित राशि की वसूली हेतु पृथक से सूचित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया था।

2- तदक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली-1997, जिसके अनुरूप आपको शासकीय आवास आवंटित है, के प्रस्तर-05 की व्यवस्थानुसार, शासनादेश सं०-2417/2004, दि० 16.11.2004 द्वारा निर्धारित लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेंट के अनुसार आपको आवंटित शासकीय आवास का अध्यारोपित किराया निम्नवत् है :-

A आवासीय पता	B आवास का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	C आवास में अध्यासन अवधि का विवरण	D 31, अक्टूबर, 2016 तक कुल अध्यासन अवधि	E शासनादेशानुसार लिविंग एरिया के आधार पर निर्धारित फ्लैट रेंट (रु० में)	F कुल अध्यारोपित किराया (रु० में) $F = D \times E$
17-न्यू कैन्ट रोड, देहरादून।	303.71	25, फरवरी, 2002	14 वर्ष 08 माह 04 दिन	1,000.00/माह	1,76,132.00

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आवंटित शासकीय आवास के अध्यारोपित किराये की राशि का भुगतान मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी० एस० नपलच्याल)
सचिव।

संख्या: 1477/xxxii-2-2016-3(31)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन / मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2- सचिव, विधानसभा सचिवालय, /सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/राज्य सम्पत्ति अनु-01 एवं 03/गोपन(मंत्रिपरिषद्) विभाग/सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अध्यारोपित किराये की राशि को प्राप्त करते हुए, नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- एन०आई०सी०, देहरादून/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय शर्कर पाण्डेय)

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

